जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 313 प्रभात चूरू, शुक्रवार 13 मार्च, 2026 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

ट्रम्प अब किसी भी तरह से खाड़ी देशों के युद्ध से पिंड छुड़ाना चाहते हैं

इसका कारण है कि इस युद्ध का अगर कोई एक शिकार है, तो वह है ट्रम्प का बड़बोलापन

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मार्च। जैसा कि हर युद्ध में होता है, यहां भी अलग-अलग दावे और कहानियां सामने आ रही हैं और जमीन पर वास्तव में क्या हो रहा है, यह समझना दिन-ब-दिन कठिन होता जा रहा है।

स्थिति और गंभीर हो गई है, क्योंकि ईरान ने अब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और इज़रायल तथा तेल अवीव शहर पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा तेल उद्योग की क्षमताओं पर लगातार हमले वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संकट को और बढ़ा रहे हैं।

तेल की कीमतें बुधवार को कुछ घटीं, पर गुरुवार को फिर बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। यह तब हुआ, जब कई देशों ने अपने रणनीतिक तेल भंडार से बड़ी मात्रा में तेल जारी किया था। ईरान का दावा है कि यदि होर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह बंद हो जाता है तो तेल की कीमतें जल्द ही 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं।

- ट्रम्प ने वादा किया था, कि वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में आवागमन को, अमेरिकी सेना की ''एस्कॉर्ट सेवा'' उपलब्ध कराकर खुलवा देंगे, पर अमेरिका की नौसेना, यह ''एस्कॉर्ट सेवा'' प्रदान करने के लिये कतई तैयार नहीं है।
- ट्रम्प ने यह भी दावा किया था कि ''स्टॉक मार्केट में भाव इतने ऊंचे पहुंचेगे, जितना पहले कभी नहीं पहुंचे। पर सच्चाई जो सामने आई, वह यह है कि जब से खाड़ी युद्ध शुरु हुआ है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स के भाव गिरते ही जा रहे हैं।
- ट्रम्प ने यह भी सार्वजनिक घोषणा की थी कि उनके टैरिफ बढ़ाने से विश्व में कॉम्पटीशन बढ़ेगा, तथा इस ''कॉम्पटीशन'' का लाभ अमेरिका को मिलेगा तथा उसका निर्यात बढ़ेगा, पर हुआ उल्टा, युद्ध के बाद व्यापार व लेनदेन में जोखिम बढ़ा और इससे डॉलर की एक्सचेंज रेट बढ़ी, और इससे अमेरिकी माल की विश्व के व्यापार में ''कॉम्पटीशननैस'' और बढ़ गई।

इससे तेल की कीमतें सामान्य करने के डॉनल्ड ट्रंप के दावे पूरी तरह गलत साबित होते दिख रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि रणनीतिक तेल भंडार से बड़े पैमाने पर तेल जारी करने और होर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने के लिए दबाव बनाने से तेल की कीमतें तेजी से गिर जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

ईरान ने दावा किया है कि उसने होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे कम से कम बारह जहाजों को नष्ट कर दिया है। वहीं, अमेरिका का कहना है कि उसने होर्मुज़ स्ट्रेट में ईरानी नौसेना के करीब 16 जहाज और उतनी ही संख्या में बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाज डुबो दिए हैं।

ईरान ने स्ट्रेट में जगह-जगह बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जिससे इस मार्ग से जहाजों का गुजरना बेहद खतरनाक हो गया है।

इन अलग-अलग दावों में सबसे नाटकीय अंतर अमेरिका और इज़राइल जैसे दो प्रमुख पक्षों के बीच दिखाई दे रहा है। जहां अमेरिका दोनों सहयोगियों की सैन्य कार्रवाई को बड़ी सफलता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, वहीं इज़राइल यह संकेत दे रहा है

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान की तीन शर्तें

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मार्च। तेहरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए तीन शर्तें रखी हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़श्कियन ने शर्तों को बताते हुए कहा कि किसी भी समाधान में ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता देनी होगी और यह गारंटी होनी चाहिए कि देश को भविष्य में हमलों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में, पेज़श्कियन ने युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की भी मांग की।

- पहली है, ईरान के वैध अधिकारों को स्वीकृति मिले, दूसरी है, दोबारा हमला नहीं करने की गारंटी और तीसरी है, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवज़ा दिया जाए।

उन्होंने लिखा, ''रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात करते हुए, मैंने क्षेत्र में शांति के लिए ईरान की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस युद्ध, जिसे कि ज़ायोनिस्ट शासन और अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है, को समाप्त करने का एक मात्र तरीका है, ईरान के वैध अधिकारों की स्वीकृति, मुआवजे का भुगतान, और भविष्य में आक्रमण से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका -इज़रायल की सदाबहार ''दोस्ती'' में दरार उत्पन्न हो रही है खाड़ी युद्ध से

युद्ध के लम्बा चलने के दोनों देशों के लक्ष्य भिन्न हैं, यह उजागर होने लगा है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मार्च। यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा खिंचता है, तो डॉनल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीतिक प्राथमिकताओं (स्ट्रैटेजिक प्रायॉरिटीज़) में जो अंतर है, वो धीरे-धीरे अमेरिका और इज़रायल के बीच इस समय नज़र आ रहे मौजूदा राजनीतिक तालमेल पर दबाव डाल सकता है।

मुद्दे का मूल कारण दोनों देशों की रणनीतिक सोच में अंतर है। इज़रायल के लिए ईरान के साथ टकराव को अस्तित्व से जुड़ी एक सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा जाता है, जो दशकों में विकसित हुई है। इज़राइली नेता कहते हैं कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएँ, मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय संगठनों, जैसे हिज़्बुल्लाह और हमास को दिया गया समर्थन एक दीर्घकालिक खतरा है, जिसे सीमित सैन्य कार्रवाई से खत्म नहीं किया जा सकता। इस नजरिये से देखा जाए तो ईरान की क्षमता को कमजोर करने और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने के लिए सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक दबाव लगातार बनाए रखना जरूरी है। इसलिए इज़रायल के लिए एक लंबा अभियान, भले ही महंगा हो, एक ऐसी रणनीतिक लड़ाई का हिस्सा माना जाता है, जिसका परिणाम आने वाले वर्षों में देश की सुरक्षा को तय करेगा।

- इज़रायल का मानना है, ईरान के ''न्युक्लियर प्रोग्राम'' व क्षेत्रीय ''आतंकवादी गिरोहों'', जैसे हिजबुल्ला व हमास की गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए लम्बा व दीर्घकालीन युद्ध जरुरी है।
- दूसरी ओर अमेरिका का सोच है, छोटी क्षेत्रीय सैन्य कार्यवाही ही होनी चाहिये, क्योंकि लंबा युद्ध यूरोपीय देशों व अमेरिका के मित्र व सहयोगी देशों के हित में नहीं है, क्योंकि बिना ऑयल के व्यापार के इन देशों की इकॉनमी डावांडोल हो जाती है और अमेरिका इन देशों से भी बनाकर रखना चाहता है तथा इज़रायल की खातिर वह अन्य देशों से बिगाड़ना नहीं चाहता।
- यह सोच का फेर, जो अमेरिका व इज़रायल के बीच अभी दबा हुआ है, और स्पष्ट हो जायेगा, अगर युद्ध कुछ लम्बा खिंचा और यह इज़रायल व अमेरिका के सम्बंधों में खटास ही नहीं कटुता भी ला सकता है।

दूसरी ओर, अमेरिका आम तौर पर पश्चिम एशिया के संघर्षों को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। हालांकि वॉशिंगटन इज़रायल का सबसे करीबी सुरक्षा साझेदार है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन अक्सर क्षेत्रीय युद्धों को लंबे और महंगे सैन्य अभियानों में बदलने से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए तीन शर्तें रखीं

पर ट्रंप अभी भी युद्ध के सम्बंध में भ्रमित तथा मिश्रित संकेत दे रहे हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मार्च। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भले ही ईरान के साथ सैन्य संघर्ष के समाप्त होने के संकेत दिए हों, लेकिन फिलहाल युद्धविराम की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ज्ञातव्य है कि युद्ध को 13 दिन हो गए हैं।

इसका कारण है ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन द्वारा रखी गई तीन कड़ी शर्तें। पहली, भविष्य में अमेरिका और इज़रायल की ओर से किसी भी हमले के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गारंटी। दूसरी, ईरान के वैध अधिकारों की मान्यता और तीसरी है, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई या मुआवज़े का भुगतान। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा, ''ज़ायोनी शासन और अमेरिका द्वारा शुरू किए गए इस युद्ध को खत्म करने का यही एकमात्र तरीका है।''

- ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में जो भी लक्ष्य थे सब हासिल हो गए अब कुछ बचा नहीं है तो युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले चार लक्ष्य तय किए थे, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का खात्मा, ईरान की नौ सेना का विनाश, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करना और हमास, हूती व हिजबोल्ला को मदद देने की सामर्थ्य खत्म करना।
- वास्तविक हालात देखें तो अमेरिका इनमें से दो ही लक्ष्य किसी हद तक प्राप्त कर पाया है, एक तो परमाणु निरस्त्रीकरण, दूसरा ईरान की नौसेना का खात्मा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने भी युद्ध समाप्त करने को लेकर मिश्रित संकेत दिए हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ओम बिड़ला स्पीकर की कुर्सी पर लौटे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मार्च। ओम बिड़ला गुरुवार को लोकसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर वापस आ गए। एक दिन पहले विपक्ष ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसे खारिज कर दिया गया था।

- स्पीकर की कुर्सी पर लौटकर ओम बिड़ला ने कहा कि वे सभी को बोलने की अनुमति देते हैं पर नियमों के तहत ही बोला जा सकता है।

संसद में बोलते हुए, बिड़ला ने पक्षपात के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ''कुछ लोगों ने मुझ पर कुछ सांसदों को संसद में बोलने से रोकने का आरोप लगाया। लेकिन मैं यह स्पष्ट

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

होर्मुज़ स्ट्रेट से होता हुआ जहाज मुंबई बंदरगाह पहुंचा

लाइबेरिया के झंडे वाला यह जहाज तेल लेकर भारत आ रहा था, इसका कैप्टन भी भारतीय है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 12 मार्च। मध्य पूर्व में बढ़ते तनावों के बीच, सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आये लाइबेरिया के ध्वज वाला एक टैंकर मुंबई बन्दरगाह पर पहुंच गया है। यह अमेरिका-इजरायल के ईरान के खिलाफ युद्ध के बीच खाड़ी जलमार्ग को सुरक्षित रूप से पार कर भारत पहुंचने वाला पहला टैंकर बन गया है। शेनलॉन्ग सूज़मैक्स तेल टैंकर, जिसका कप्तान एक भारतीय था, दो दिन पहले ही संघर्षग्रस्त होर्मुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) से होकर गुजरा था।

ईरान द्वारा शिपिंग यातायात और ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किये जा रहे लगातार हमलों के कारण, गुरुवार को तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, क्योंकि इस्लामिक गणराज्य ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले लगातार हो रहे हैं और युद्ध के समाप्त होने का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। भारत की ओर जा रहा यह जहाज, कथित रूप से पहचान से बचने के लिए कुछ समय के लिए अपना संकेत बंद करके युद्ध प्रभावित समद्री क्षेत्र को पार कर गया।

- जहाज ने जब युद्ध ग्रस्त क्षेत्र में प्रवेश किया तब न केवल लाइट बंद कर दी बल्कि ट्रैकिंग सिस्टम भी ऑफ कर दिया।
- अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ट्रैफिक सिस्टम ऑन रखना अनिवार्य है, लेकिन विलक्षण परिस्थितियों में ट्रैकिंग सिस्टम बंद किया जा सकता है।

लाइबेरिया के ध्वज वाला यह जहाज, जिसमें कच्चा तेल भरा था, 1 मार्च को सऊदी अरब के रास तनुरा बंदरगाह से रवाना हुआ था। समुद्री ट्रैकिंग डेटा ने दिखाया कि जहाज के संकेत 8 मार्च को होर्मुज़ स्ट्रेट के अंदर अंतिम बार निगरानी प्रणालियों में दिखे थे, उसके बाद ये गायब हो गए। इसका मतलब है कि चालक दल ने जहाज के ऑटोमैटिक आईडेन्टिफिकेशन सिस्टम (ए आई एस) और ट्रांसपौंडरों को उस समय बंद कर दिया था, जब वे पानी के खतरनाक हिस्से से गुजर रहे थे।

उच्च जोखिम वाले क्षेत्र को सफलतापूर्वक पार करने के बाद, जहाज अगले दिन फिर से समुद्री ट्रैकिंग सिस्टम्स पर फिर से दिखाई दिया, जब वह भारत की ओर अपनी यात्रा जारी रखे हुए था। शिपिंग कंपनियां अक्सर इस तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, जिसे ''डार्क होना'' भी कहा जाता है, ताकि उन्हें दुश्मनों द्वारा निशाना बनाए जाने या ट्रैक किए जाने का खतरा न हो। लेकिन यह उपाय केवल असाधारण परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)